भीड़ से अलग निकलना ही है जिंदगी।
– अज्ञात

पाकिस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास

पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों के साथ एक दिक्कत यह भी रही कि आधुनिक जीवन मूल्यों की नुमाइंदगी करने में उनकी वैसी दिलचस्पी नहीं थी, जैसी तुर्की, इजिप्ट और इराक के सैनिक तानाशाहों ने सत्ता पर कब्जा करने के बाद दिखाई थी।

संजय भट्ट

परवेज मुशर्रफ अपने देश के पहले ऐसे पूर्व तानाशाह बन गए हैं जिन्हें राजद्रोह के अपराध में मौत की सजा सुना दी गई। विशेष अदालत की तीन जजों वाली बेंच ने दो–एक के बहुमत से मंगलवार को उनके लिए यह सजा मुकर्रर की। हालांकि मुशर्रफ 2016 से ही स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दुबई में रह रहे हैं। इस बात की संभावना कम है कि वह स्वदेश लौटेंगे और उन्हें सुनाई गई इस सजा पर अमल हो पाएगा। बावजूद इसके, पाकिस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में यह फैसला मील का पत्थर माना जा रहा है। कोर्ट ने मुशर्रफ पर लगाए गए इस आरोप को सही पाया कि 2007 में उन्होंने संविधान को निष्प्रभावी करते हुए देश पर असंवैधानिक रूप से आपातकाल लाद दिया था। हालांकि ऐसा करने वाले मुशर्रफ पाकिस्तान के अकेले सैन्य प्रमुख नहीं हैं।

सैन्य शासन का साया इस पड़ोसी देश पर इस कदर छाया रहा कि लोकतंत्र वहां ढंग से पनप ही नहीं पाया। 72 साल के इतिहास में आधे से ज्यादा समय तक वहां सेना ही शासन में रही। स्वाभाविक रूप से स्थिति ऐसी हो गई कि देश की नौकरशाही में चुनी हुई सरकारों को लेकर वह इज्जत नहीं पैदा हुई, जो एक कामकाजी व्यवस्था के लिए जरूरी है। जब भी कोई निर्वाचित सरकार सत्ता में आई, उसे 'फिल द गैप अरेंजमेंट' के रूप में लिया गया और इंतजार किया जाता रहा कि कब सेना उसको बेदखल कर सत्ता अपने हाथ में लेती है। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों के साथ एक दिक्कत यह भी रही कि आधुनिक जीवन मूल्यों की नुमाइंदगी करने में उनकी वैसी दिलचस्पी नहीं थी, जैसी तुर्की, इजिप्ट और इराक के सैनिक तानाशाहों ने सत्ता पर कब्जा करने के बाद दिखाई थी।

मुस्तफा कमाल पाशा, गमाल अब्दुल नासिर और सद्दाम हुसैन के शासन में इन तीनों देशों ने धार्मिक कट्टरपंथ से काफी हद तक मुक्ति पाई थी। मगर पाकिस्तानी सैन्य तानाशाहों ने न केवल कट्टरपंथियों से जुगलबंदी बनाए रखी बल्कि जनरल जिया उल हक ने तो वहां शरिया कानून लागू कर दिया। नतीजा यह रहा कि पाकिस्तान लोकतंत्र से तो वंचित रहा ही, सामाजिक–आर्थिक सुधारों से भी अछूता बना रहा। स्वाभाविक रूप से वहां मध्यम वर्ग नहीं विकसित हो पाया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद माना जाता है।

अच्छी बात इस सिलसिले में यह है कि धीरे–धीरे ही सही, पर 21 वीं सदी में वहां लोकतांत्रिक चेतना मजबूत होती दिखी है। इसमें न्यायपालिका की खास भूमिका रही है। मुशर्रफ के शासनकाल में वकीलों की अगुआई में चले आंदोलन ने सैन्य तानाशाही के खिलाफ माहौल बनाने में काफी मदद की और अब विशेष अदालत का ताजा फैसला इस लिहाज से अहम है कि वहां के संभावित सैनिक शासकों में यह थोड़ी हिचक पैदा कर सकता है। यह न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए सुकून की बात होगी, हालांकि एक स्थायी लोकतंत्र बनने के लिए पाकिस्तान को और भी बहुत कुछ करना होगा।

संवेदना

मनमोहन। संवेदना जिसका अर्थ होता है सुख–दुख का अनुभव या ज्ञान या आप प्रतीति भी कह सकते हैं। संवेदना मनुष्य की समझ,ज्ञान, विवेक का ही पर्याय होती है। मनुष्य की वैचारिक दृष्टि में सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ संवेदना में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। देखिए वास्तविक जगत किस तरह आज काल्पनिक हो रहा है। वास्तविकता कहां और कैसे प्रमाणित की जाए ? भ्रम और दुविधा में अंतर कैसे किया जाए? किस तरह संवेदनहीन को संवेदनशील किया जाए ? कोई तो उपाय हो जो व्याकुल आत्मा को शांत कर जाए... कहां और किसे खोजें जो, यथार्थ के सैलाब को सोख पाए। मन अधीर है क्यों हर संवेदनशील विकल्प पर मतभेद व विरोध हो जाए ? यह कैसी विकास की सीढ़ी मेरा देश चढ़ रहा है।

संपादकीय

नए सिरे से बातचीत

दुनिया के अस्तित्व से जुड़े इस मुद्दे पर तीन महाशक्तियों के बीच नए सिरे से बातचीत सबको सुकून देने वाली है। हालांकि यह सिर्फ शुरुआती संकेत है और अभी इसके साथ बहुत सारे किंतु–परंतु जुड़े हुए हैं।

फ्रांस और ब्रिटेन जैसी बड़ी एटमी ताकतें इस संभावित समझौते की परिधि से बाहर हैं। भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इस्राइल जैसी घोषित–अघोषित परमाणु शक्तियों को इसमें शामिल करना तो अभी काफी दूर की कौड़ी है। बावजूद इसके, यह पहल उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। शीतयुद्ध के तनावपूर्ण दौर से निकलने की जद्दोजहद में दुनिया ने परमाणु निरस्त्रीकरण को एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था। आईएनएफ (इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज) ट्रीटी जैसे समझौतों के जरिए इस ओर कुछ महत्वपूर्ण कदम भी बढ़ाए गए थे। अमेरिका और रूस ने इस समझौते के तहत जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और शॉर्ट, मीडियम व इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट किए। बाद में शीतयुद्ध का दौर बीत जाने और कई नए परमाणु संपन्न देशों के सामने आ जाने से हालात बदले, फिर भी सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के ही पास थे। लिहाजा इनकी अगुआई में दुनिया परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद बनी हुई थी। अमेरिका के अंदर इस केमिस्ट्री के कुछ अलग मतलब भी निकाले जाते हैं, लेकिन इसकी बदौलत दुनिया अगर परमाणु हथियारों से जुड़े खतरों पर राहत की सांस लेती है तो कम से कम इस योगदान के लिए दोनों नेताओं की आपसी समझदारी का स्वागत तो किया ही जाना चाहिए।

यह वाकई चौंकाने वाला निर्णय है क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका की अफगान नीति में बदलाव कर हाल में ही वहां सैनिकों की नई कुमुक भेजी थी।

अफगान नीति में बदलाव

रश्मि वर्मा

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सीरिया और अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। पहले उन्होंने सीरिया पर जीत का ऐलान किया और कहा कि उनके सैनिक वहां से वापस आएंगे। उसके अगले ही दिन उन्होंने अफगानिस्तान से भी अपने सैनिक लौटाने का फैसला किया। यह वाकई चौंकाने वाला निर्णय है क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका की अफगान नीति में बदलाव कर हाल में ही वहां सैनिकों की नई कुमुक भेजी थी। वैसे सैनिकों की वापसी इस अर्थ में सकारात्मक ही कही जाएगी क्योंकि इससे सैनिकों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। लेकिन मुश्किल यह है कि अमेरिका ने जिस मकसद से सैनिक भेजे थे, वह पूरा नहीं हुआ है, खासकर अफगानिस्तान में तो चीजें और ज्यादा उलझ गई हैं।

जहां तक सीरिया का प्रश्न है तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस्लामिक स्टेट के जिहादियों के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे कुर्दिश लड़ाके अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी से अपने को कमजोर महसूस कर सकते हैं। हालांकि एक राय यह भी है कि अमेरिका की कोई खास भूमिका वहां थी ही नहीं। उलटे उस पर आईएस को खड़ा करने का ही आरोप लगता रहा है। अफगानिस्तान पर वापस लौटें तो यहां से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का दक्षिण एशिया पर गहरा असर पड़ सकता है। पिछले 17 सालों से अमेरिकी सेना वहां बैठी हुई है।

नए फैसले के मुताबिक अगले कुछ महीनों में वहां मौजूद सभी 14,000 अमेरिकी सैनिक धीरे–धीरे करके वापस बुला लिए जाएंगे। जमीनी सच यह है कि अफगानिस्तान को आतंकवाद से निजात नहीं मिली है, न ही वहां राजनीतिक प्रक्रिया मजबूत हो सकी है। अमेरिका की कोशिश किसी तरह वहां से निकल जाने की है क्योंकि ट्रंप की आक्रामक नीति का कोई फायदा नहीं हुआ, उलटे तालिबान की ताकत में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई है और कहा जा रहा है कि देश के 40 से 50 फीसदी हिस्से पर उसका कब्जा हो चुका है। दूसरी तरफ देश का पूर्वी हिस्सा आईएस के कब्जे में आता जा रहा है।

अमेरिका ने तालिबान से बातचीत की कई कोशिशें करके देख लीं लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने की एक वजह रूस भी है, जो न सिर्फ वहां आईएस से लड़ने में तालिबान की मदद कर रहा है बल्कि वहां शांति स्थापित करने के लिए अपने तरीके से प्रयास भी कर रहा है। पिछले महीने अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच बैठक भी रूस की पहल पर ही संभव हुई। बहरहाल, अमेरिकी फैसले से भारत की फिक्र बढ़ गई है। आने वाले दिनों में वहां अराजकता बढ़ सकती है, जिससे हमारी परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। फिलहाल सतर्क होकर स्थितियों पर नजर रखनी होगी।

अष्टयोग-4897

	3	2		6		5
	33		35		28	
1		5	4			2
	35		35	7	32	
7		6		4		1
	33		31		30	4
3		4		2	5	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है.खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं.गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी.सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4896 का हल

6	1	4	7	2	5	3
5	33	3	35	1	27	7
4	3	7	5	6	1	2
3	29	2	45	7	33	6
1	3	6	7	5	2	4
2	29	1	33	4	30	5
7	4	5	2	3	6	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

इन्हें कुछ न कहो, ये सिर्फ स्क्रीन के हीरो हैं

उपमा सिंह। 'जब आग लगी हो, तो न्यूट्रल रहने का मतलब ये होता है सर कि आप उनके साथ खड़े हैं, जो आग लगा रहे हैं।' यह जाति, धर्म, समुदाय, लिंग या धर्मस्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध करने वाली संविधान की धारा 15 पर आधारित फिल्म आर्टिकल 15 का डायलॉग है। लेकिन बॉलिवुड स्टार्स की बात करें, तो होता हमेशा यही है। देश की राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे की बात हो, तो इंडस्ट्री के बड़े–बड़े लीजेंड्स और सुपरस्टार्स खामोश हो जाते हैं। जैसा कि अभी हो रहा है, देश में नागरिक संशोधन कानून लागू किए जाने को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह–जगह छात्र सड़कों पर हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। लेकिन हमारे परदे के तमाम बड़े हीरोज चुप्पी साधे तमाशबीन बने हुए हैं और रोजमर्रा की तरह महज एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए दिल्ली और आईरिश बैंड यू 2 की शान बढ़ाने नवीं मुंबई तक पहुंच जाने वाले इन स्टार्स के पास देश के इस अहम मसले पर कुछ भी कहने के लिए न शब्द है, न वक्त।